

जम्मू-कश्मीर के नवासिधियों के ललल परवलर पहचान पत्र

प्रललललस के ललल:

AADHAR लक्षुतल जन वतलरण प्रणाली, NFSA

मेनुस के ललल:

कल्याणकारी योजनाओं हेतु पारवलरकल डेटाबेस - दक्षता, महत्त्व और चुनौतललें

चरुा में कूलें?

भारत सरकार ने हाल ही में केंद्र शासतल प्रदेश जम्मू और कश्मीर के नवासलधियों के ललल एक **परवलर पहचान पत्र** लाने का फैसला कलल है ।

परवलर पहचान पत्र:

■ परचलल:

- FPP अद्वतललतल **8-अंकलतल अक्षरांकलतल नंबर (पैन कार्ड की तरह)** वाला एक पहचान पत्र होगा, जललमें **परवलर के मुखलतल के माधुतल** से प्रतुतुतल परवलर और उसके सदसुतुओं की पहचान की जाएगी ।
- यह केंद्रशासतल प्रदेशों में प्रतुतुतल परवलर और वुतुतुतल के ललल एकल पहचान-पत्र होगा, आधार कार्ड के वलरलतल इसमें केवल एक वुतुतुतल के बारे में जानकारी होती है ।

■ ववलरण और लकललल:

- इस कार्ड में परवलर के सभी सदसुतुओं का ववलरण होगा, जललमें उनके नाम, आयु, तुतुतुतल, रोज़गार की सुथतलल आदल शामिल हैं और इसे परवलर के प्रमुख के **आधार (AADHAR)** और बैंक खाता संखुतल से जोड़ा जाएगा ।

■ महत्त्व:

- **कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर वतलरण:** FPP का उददेशुतल जम्मू-कश्मीर में परवलरों का एक प्रामाणकल, सतुतुतलपतल और वशलुवसनीतल डेटाबेस बनाना है ताकल **पात्र लाभार्थलतुओं की कल्याणकारी योजनाओं तक तुरतल और पारदरशी पहुँच सुनशलुतल की जा सके ।**
- **सहज प्रतुतुतल लाभ अंतरण:** इस तरह की प्रणाली नुतुनतलमानवीतल हसुतक्षेप के साथ उनके बैंक खातों में लाभों के सीधे अंतरण की सुवधल प्रदान करेगी ।
- **डुपलकलसी को समाप्त करना:** डेटाबेस डुपलीकेट राशन कार्ड और आधार की पहचान करने और इनहें हटाने में भी मदद करेगा **एक्सरकार को उन परवलरों की पहचान करने में मदद करेगा जललके पास कई शकलषतल तुवा हैं, लेकनल नौकरी नहीं है ।**
- **डेटा का सुवत: अदुततन:** डेटाबेस में जानकारी (जनुम, मृतुतु और ववलह) लगातार और सुवचालतल रूत से अदुततन की जाएगी एवं लुगों को ऐसे उददेशुतुओं के ललल सुथानीतल अधकलरलतुओं के पास नहीं जाना पड़ेगा ।
 - यह प्रामाणकल, अदुततन जनसंखुतल डेटा के आधार पर **सरकार की तुतलनीतल में भी मदद करेगा ।**

■ FPP के संबंध में असहमतल:

- सरकार के अनुसार परवलर की सहमतल से ही डेटाबेस बनाया जाएगा । हालाँकल **परवलर कार्ड रखने के ललल सहमतल नहीं देने वाले परवलरों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में वुतलवहारकल कठनलतुतुओं का सामना करना पड़ सकता है ।**
- **राषुटुरीतल खादुतल सुरक्षा अधनलतुतल के तहत लक्षतल सारवजनकल वतलरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System- PDS)** के माधुतल से सबसुडल वाले राशन, मुफुत चकलतलसल उपचार, वृदुधलवसुथल/वधलल/पारवलरकल पेंशन, तुगुरवाद के पीड़तुतुओं को सहातल, छातुरवृतुतल आदल सभी को परवलर पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा ।

■ FPP के खलललफ तरक:

- वलकषी दलों ने FPP के वुतलर की आलुचना करते हुए इसे **कश्मीरलतुओं पर नज़र रखने के ललल 'नगलरानी उपकरण' के रूत में वरणतल कलल है ।**
 - यह जम्मू-कश्मीर के लुगों पर वशलवास की कमी के प्रतुीक के रूत में **"अद्वतललतल परवलर आईडी"** का दावा करता है ।
- प्रसुतावतल तुनकल आईडी की समय और संसाधनों की बरुादी के रूत में आलुचना की गई थी अरुथलतु **एक्समान प्रणाली के रूत में इसकी आवश्यकता नहीं थी कूलेंकल आधार पहले से मौजूद है ।**
- चीनी संसुथलओं दुवलर हाल ही में साइबर और रैसमवेयर हमलों के मददेनज़र नवासलधियों के वुतुतुतलगत डेटा की रक्षा करने में सरकार की

अन्य राज्यों में समान परिवार डेटाबेस:

- कई अन्य राज्यों ने समान डेटाबेस प्रस्तावित किये या बनाए हैं; परिवार पहचान पत्र की अवधारणा को लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य था।
- पंजाब ने वर्ष 2021 में उन परिवारों को लाभ के प्रत्यक्ष हस्तांतरण हेतु ऐसी प्रणाली शुरू की जो सरकार की विभिन्न सामाजिक सेवा योजनाओं के लिये पात्र हैं।
- नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी तरह के उद्देश्यों के लिये यूपी परिवार कल्याण कार्ड लॉन्च करने का निर्णय लिया।
- राजस्थान राज्य ने भी "जन आधार योजना" शुरू की है, जिसका उद्देश्य एक परिवार से एक व्यक्ति की पहचान करना है और यह राज्य में संचालित अपनी तरह की एकमात्र योजना है, जिस पर सभी प्रकार की नकदी के साथ-साथ गैर-नकदी लाभ की प्राप्ति होती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वरित वरष के प्रश्न (PYQ)

????????

प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत किये गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. केवल 'गरीबी रेखा से नीचे (BPL)' की श्रेणी में आने वाले परिवार ही सबसिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं।
2. राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से घर की सबसे बड़ी महिला, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, घर की मुखिया होगी।
3. गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद छह महीने तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी का 'टेक-होम राशन' मलितल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. अनाज वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं? (2019)

प्रश्न. नीति प्रक्रिया के सभी चरणों में, जागरूकता और सक्रिय भागीदारी के अभाव के कारण कमजोर वर्गों के लिये लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं का प्रदर्शन इतना प्रभावी नहीं है। चर्चा कीजिये। (2019)

प्रश्न. भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? इसे प्रभावी और पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है? (2022)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस